

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 09 जनवरी 2026 वर्ष-8,अंक-313 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

तेलंगाना में कार डिवाइडर से टकराई, 4 छात्रों की मौत

■ एक छात्रा घायल, बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे सभी



एजेंसी
तेलंगाना। रंगा रेड्डी जिले के चेवेल्ला इलाके में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कन्नडकबिजनस स्कूल के चार छात्रों की मौत हो गई। हादसे में एक छात्रा घायल है। इसकी हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक कार डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ में घुस गई। पुलिस ने बताया का हादसा रात करीब 1:30 बजे मोकौला थाना क्षेत्र में हुआ। सभी छात्र दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। स्पीड ज्यादा तेज होने के कारण ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया। पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों और घायल की पहचान कर ली गई है। मृतकों के नाम कारगयाला सुमित (20), निखिल (20), देवाला सूर्या तेजा (20) और बलमूरी रोहित (18) हैं। घायल छात्रा का नाम सुकुरी नक्षत्रा है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया जिसका इलाज जारी है।

'आजम खां बीमार...जेल में नहीं मिल रही सुविधा

■ बेड तक नहीं दिया, मुलाकात के बाद बोलीं: पत्नी तजीन फात्मा



एजेंसी
रामपुर। सपा नेता आजम खां से उनकी पत्नी तजीन फात्मा ने जेल में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि आजम खां इन दिनों बीमार हैं। उनको जेल में सुविधा नहीं मिल रही है। सपा नेता आजम खां से उनकी पत्नी तजीन फात्मा ने जेल में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि आजम खां इन दिनों बीमार हैं। उनको जेल में सुविधा नहीं मिल रही है। मार इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी तजीन फात्मा ने अपने बड़े बेटे अदीब आजम के साथ जेल में बंद सपा नेता से मुलाकात कर चुके हैं। आजम इन दिनों बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैर कार्ड केस में सजा मिलने के बाद रामपुर जेल में बंद है। उनको कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे अग्निवेश

एजेंसी
मुंबई। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 जनवरी 2026 को अस्पताल में ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। पिता अनिल अग्रवाल ने रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अनिल ने लिखा, "हमें लगा था कि बुरा वक्त बीत चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर



था।" उन्होंने अपने बेटे को याद करते हुए इसे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया। वे बेटे से किए वादे को निभाते हुए अपनी निजी कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल अग्रवाल के पोस्ट रिप्लाई करते हुए 'पर लिखा "अग्निवेश अग्रवाल का अचानक चले जाना बहुत झकझोर देने वाला और दुखद है। आपके इस भावुक संदेश से

आपके गम की गहराई साफ दिख रही है। दुआ है कि आप और आपका परिवार लगातार हिम्मत और ताकत पाएं। ओम शांति।" अग्निवेश अग्रवाल का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। उनकी शुरूआती पढ़ाई अमेरिका के मेगो कॉलेज से हुई थी। अग्निवेश अग्रवाल की शादी की जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शादी 2001 में पूजा बांगर से हुई थी। पूजा, श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि मोहन बांगर की बेटी हैं। अग्निवेश की बहन प्रिया अग्रवाल हेब्वर हैं, जो अभी हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

जनगणना 2027-पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा

घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे, ये काम 30 दिन में पूरा होगा

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से शुरू करने के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। MHA ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 1 अप्रैल से देशभर में सभी मकानों और परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही परिवारों की अन्य जानकारी भी



इकट्ठी की जाएगी, ताकि जनसंख्या गिनने की मजबूत तैयारी हो सके। सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प

भी दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, जो अब 2027 में पूरी होगी। सरकार ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी

तरह डिजिटल होगी। करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल एप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। मोबाइल एप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी। ये ऐप Android और iOS दोनों पर काम करेंगे। जाति से जुड़ा डेटा भी डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति की गिनती शामिल होगी। इससे पहले अंग्रेजों के समय 1931 तक जाति आधारित जनगणना हुई थी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने

सुप्रीम कोर्ट बोला: कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं, इसलिए काटते हैं

वकील बोले: देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर, हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत

एजेंसी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर गुरुवार को लगातार सुनवाई के दौरान एनिमल वेलफेयर की दूसरे दिन ढाई घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। इस पर एक वकील (कुत्तों के फेवर वाले) ने इनकार किया। फिर जस्टिस ने कहा- अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्यों ने जो आंकड़े दिए हैं। उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि नगर पालिकाओं की तरफ से कितने शेल्टर चलाए जाते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं। इनमें से हर

एक में 100 कुत्ते रह सकते हैं। हमे इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एनिमल वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट सीयू सिंह ने कुत्तों को हटाने या शेल्टर होम भेजने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी। इस पर कोर्ट ने मजकिया अंदाज में कहा- तो क्या बिल्लियां ले आए? इस मामले पर पिछले 7 महीनों में छह बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तब शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए।



याचिकाकर्ता के एक वकील ने कहा हर पालतू कुत्ते का मालिक होता है। जबकि आवारा कुत्ते का कोई मालिक नहीं होता। न ही यह राज्य की जिम्मेदारी है। हालांकि राज्य का काम वैक्सीनेशन वगैरह देना है। ABC नियम ऐसे होने चाहिए कि भरे घर

तक का रास्ता सुरक्षित रहे। वकील (कुत्तों को हटाने के पक्ष में) ने कहा कि अदालत का आदेश सिर्फ संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए। बल्कि उसे रिहायशी इलाकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। कुत्ते को समझाना (काउंसिलिंग) संभव नहीं है,

लेकिन कुत्ते की देखभाल करने वाले या मालिक को समझाया जा सकता है। हर डॉग लवर और एनजीओ को याचिका लगाने में एक तय राशि जमा करनी होती है। इस शर्त को हटाया जाए। इस पर कोर्ट ने हल्के अंदाज में जवाब दिया- अगर हमने यह शर्त नहीं रखी होती, तो यहां पंडाल लगाना पड़ता। कुत्तों की मॉनिटरिंग के लिए पहले उनकी गिनती जरूरी है जो आखिरी बार 2009 में हुई थी। सिर्फ दिल्ली में 5,60,000 कुत्ते थे। सेंटर्स की हाउसिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही तय संख्या में जानवरों को पकड़ा जाना चाहिए। कैपेसिटी है ही नहीं, तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? एक वकील (कुत्तों को न हटाने के फेवर में) ने कहा- दिल्ली में चूहे और बंदरों का भी खतरा है।

राजधानी की हवा खराब श्रेणी में बरकरार

■ एनसीआर में गाजियाबाद की हवा सबसे प्रदूषित



एजेंसी
नई दिल्ली। राजधानी में हवा की दिशा बदलने से वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में बरकरार है। ऐसे में बृहस्पतिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 280 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। इसमें बुधवार की तुलना में 9 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, एनसीआर में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 296 दर्ज किया गया, फेब्रिकेशन इंडेक्स 3500 श्रेणी है। वहीं, ग्रेटर नोएडा में 290, नोएडा में 294 और गुरुग्राम में 290 एक्यूआई दर्ज किया गया। सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 223 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नियंत्रण सहायता प्रणाली के अनुसार, वाहन

से होने वाला प्रदूषण 14.58 फीसदी रहा। इसके अलावा पेरिफरल उद्योग से 12.38, आवासीय इलाकों से 3.57, निर्माण गतिविधियों से 1.85 और कूड़ा जलाने की 1.27 फीसदी की भागीदारी रही। सीपीसीबी के अनुसार, बृहस्पतिवार को हवा पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चली। वहीं, अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 1050 मीटर रही। इसके अलावा, वेंटेनेशन इंडेक्स 3500 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। दूसरी ओर, दोपहर तीन बजे हवा में पीएम10 की मात्रा 205.3 और पीएम2.5 की मात्रा 116.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण निंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।

दिल्ली में पत्थरबाजी मामला: सपा सांसद से पूछताछ करेगी पुलिस

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एक्शन, नेता बोले: रिएक्शन तो होगा ही

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली में 6 जनवरी की रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर सपा सांसद मोहिल्लुल्लाह नदवी से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के बार-बार कहने के बावजूद नदवी घटनास्थल से नहीं गए और आसपास मौजूद रहे। पुलिस ने CCTV फुटेज से पत्थरबाजी में शामिल 30 लोगों और सोशल मीडिया पर मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाने वाले 10 इन्फ्लुएंसर की पहचान की है। हिंसा के मामले में 6 और गिरफ्तारियों के साथ कुल 11 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल पूरा मामला फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाने गई थी। इस बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराई जाएगी। जिससे हिंसा भड़की। पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सपा नेता एस टी हसन ने कहा कि यहां 100 साल पुरानी मस्जिद और दुकानें हैं। जब अतिक्रमण के नाम पर जुल्म किया जाएगा तो लोग कब तक विरोध नहीं करेंगे? अगर यही कार्रवाई हर जगह की जाए, तो लोग सन्न करेंगे। अगर कोई अवैध अतिक्रमण



हुआ है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में यह सब हुआ। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली की एक मस्जिद की वक्फ की जमीन के एक हिस्से को गिरा दिया गया। इस अपराध के लिए पूरी तरह से काला वक्फ (संशोधन) कानून जिम्मेदार है। 6 जनवरी की रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मस्जिद को गिराया जा रहा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पोस्ट खालिद मलिक नाम के व्यक्ति की थी। वीडियो में उसने लोगों से बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलने की अपील की थी। इसके तुरंत बाद कई लोग वहां जमा हो गए और कुछ ने पुलिस और MCD कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बौतलें फेंकीं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दूसरे कानूनों के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस ने मंगलवार रात प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। फैज-ए-इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया कि मस्जिद के बाहर की 0.195 एकड़ जमीन पर बने ढांचे अवैध हैं। उन्हें हटाया जाएगा। एमसीडी का कहना है कि अतिरिक्त जमीन पर मालिकाना या वैध कब्जे के दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। एमसीडी का यह आदेश 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया था। डिवीजन बेंच के आदेश में तुर्कमान गेट के पास मंगललीला ग्राउंड से करीब 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, जिसमें सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और एक निजी क्लिनिक शामिल हैं। मस्जिद समिति का कहना है कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है। वह इसके लिए वक्फ बोर्ड को लीज किराया देती है।

मातृभूमि से दूर बसे अपनों से भारत का सजीव संवाद

(लेखक – कांतिलाल मांडोट)

(प्रवासी भारतीय दिवस)

भारत केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कारों और साझा स्मृतियों की निरंतर धारा है। यह धारा देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि समय के साथ समुद्रों, महाद्वीपों और संस्कृतियों को पार करती हुई विश्व के कोने–कोने तक पहुँची। इसी वैश्विक विस्तार का मानवीय रूप है प्रवासी भारतीय समुदाय। इन्हीं प्रवासी भारतीयों के योगदान, संघर्ष, उपलब्धियों और भारत से उनके अटूट रिश्ते को सम्मान देने के लिए हर वर्ष नौ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष दो हजार पंद्रह के बाद से यह आयोजन हर दो वर्ष में एक बार बड़े सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाने लगा है, लेकिन दिवस के रूप में इसका प्रतीकात्मक महत्व निरंतर बना हुआ है।

नौ जनवरी की तिथि का अपना ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व है। इसी दिन वर्ष उन्नीस वीं पंद्रह में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। विदेश की धरती पर रहते हुए उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग किए, रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष किया और वहीं से एक ऐसे नेतृत्व का निर्माण हुआ, जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। गांधीजी का यह लौटना केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि विदेश में अर्जित अनुभव, ज्ञान और संघर्ष की ऊर्जा मातृभूमि के उत्थान में कितनी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। प्रवासी भारतीय दिवस इसी विचार का आधुनिक विस्तार है।

प्रवासी भारतीय दिवस का मूल उद्देश्य भारत और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के बीच सेतु बनाना है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ भावनात्मक जुड़ाव के साथ–साथ विचारों का आदान–प्रदान होता है। प्रवासी भारतीय अपने अनुभव साझा करते हैं, भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने के नए रास्ते तलाशते हैं और भारत सरकार भी उनकी अपेक्षाओं, समस्याओं तथा सुझावों को प्रत्यक्ष रूप से सुनती है। यह आयोजन यह स्पष्ट करता है कि भारत अपने नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को केवल

पासपोर्ट या निवास की परिभाषा में नहीं बँधता, बल्कि उन्हें अपनी व्यापक राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा मानता है।

वर्ष दो हजार तीन में इस सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। उस समय यह महसूस किया गया कि विश्व भर में फैले भारतीय समुदाय ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इन उपलब्धियों का लाभ केवल संबंधित देशों तक सीमित न रहे, बल्कि भारत की प्रगति में भी उनका समुचित योगदान सुनिश्चित हो। तभी से प्रवासी भारतीय दिवस एक संवाद, सम्मान और सहभागिता का उत्सव बन गया।

हाल के वर्षों में इस आयोजन का स्वरूप और अधिक व्यापक हुआ है। दो हजार पच्चीस में आयोजित अठारहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में ‘विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान’ विषय विशेष रूप से प्रासंगिक रहा। यह विषय इस बात को रेखांकित करता है कि आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना में प्रवासी भारतीयों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। निवेश, नवाचार, कौशल, वैश्विक संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से प्रवासी भारतीय दिवस के विकास लक्ष्य को गति दे सकते हैं।

इस सम्मेलन के दौरान विशेष पर्यटक रेल सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है। इसके साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रदर्शनों के माध्यम से उन भारतीयों की यात्रा को भी सामने लाया गया, जो कभी गुजरात के तटों से निकलकर ओमान, अफ्रीका और अन्य देशों में बसे। यह इतिहास केवल पलायन की कहानी नहीं है, बल्कि साहस, परिश्रम और अनुकूलन की प्रेरक गाथा है।

प्रवासी भारतीय दिवस के विमर्श में गिरमिटिया मजदूरों का स्मरण विशेष महत्व रखता है। औपनिवेशिक काल में हजारों भारतीयों को अनुबंधित मजदूर के रूप में फिजी, मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में ले जाया गया। कठिन परिस्थितियों, शोषण और अपमान के बावजूद उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा।

आज उन्हीं के वंशज उन देशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका स्मरण हमें यह सिखाता है कि भारतीय पहचान कितनी दृढ़ और जीवंत है।

प्रवासी भारतीय दिवस का एक महत्वपूर्ण पक्ष है प्रवासी भारतीय सम्मान। यह सम्मान उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने विदेशों में रहते हुए भारत की छवि को सशक्त किया, स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए कार्य किया और भारत तथा अपने निवास देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाया। यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का नहीं, बल्कि सामूहिक गौरव का प्रतीक है।

इस आयोजन की उपयोगिता अनेक स्तरों पर दिखाई देती है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रवासी भारतीय निवेश, प्रेषण और व्यापार के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हैं। विदेशों से आने वाला धन केवल परिवारों की आजीविका ही नहीं सुधारता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है। बौद्धिक स्तर पर प्रवासी भारतीय अपने ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के अनुभव भारत के साथ साझा करते हैं, जिससे देश में नई सोच और तकनीक का विकास होता है।

सांस्कृतिक दृष्टि से प्रवासी भारतीय दिवस भारत की नरम शक्ति को मजबूत करता है। योग, आयुर्वेद, भारतीय संगीत, नृत्य और त्योहारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति विश्व में सम्मान प्राप्त कर रही है। प्रवासी भारतीय इस सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी प्रवासी समुदाय विभिन्न देशों में भारत के पक्ष को समझाने और समर्थन जुटाने में सहायक सिद्ध होता है।

युवा प्रवासी भारतीय दिवस इस आयोजन का एक विशेष और दूरदर्शी आयाम है। युवा पीढ़ी, जो विदेशों में जन्मी या पली–बढ़ी है, उसके लिए भारत कभी–कभी केवल एक पारिवारिक स्मृति बनकर रह जाता है। यह विशेष कार्यक्रम उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है, भारत की समकालीन वास्तविकाओं से परिचित कराता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि भारत केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि



भविष्य की संभावनाओं से भरा देश है।

प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का महत्व केवल उत्सव तक सीमित नहीं है। यह आत्ममंथन का अवसर भी है। यह भारत को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वह अपने प्रवासी समुदाय की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पा रहा है। साथ ही यह प्रवासी भारतीयों को भी यह याद दिलाता है कि उनकी पहचान, जिम्मेदारी और योगदान केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ से जुड़ा हुआ है।

आज के वैश्वीकृत युग में जब पहचानें तेजी से बदल रही हैं, प्रवासी भारतीय दिवस स्थायित्व का प्रतीक बनकर उभरता है। यह बताता है कि दूरी भौगोलिक हो सकती है, भावनात्मक नहीं। भारत और प्रवासी भारतीयों का रिश्ता समय, राजनीति और परिस्थितियों से परे है। यह रिश्ता साझा मूल्यों, स्मृतियों और भविष्य के सपनों से बना है।

अंततः प्रवासी भारतीय दिवस भारत के उस आत्मविश्वास का उत्सव है, जो अपने नेटों और बेटियों को दुनिया में आगे बढ़ते देखकर गर्व करता है और उन्हें फिर से अपनी विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करता है। यह दिवस यह संदेश देता है कि भारत की प्रगति की कहानी अधूरी है, जब तक उसमें प्रवासी भारतीयों की सहभागिता, अनुभव और ऊर्जा शामिल न हो। यही कारण है कि प्रवासी भारतीय दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक आत्मा का उत्सव है।

(वरिष्ठ तंत्रकार, साहित्यकार, स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्यक्‍तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ‍ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

एक बेतुका आदेश

हाल के दिनों में देश की शीर्ष अदालत से लेकर आम विमर्श तक में आवारा कुत्तों का मामला सुर्खियों में रहा है। इस संवेदनशील, जटिल व विवादोत्प्रेरक मुद्दे से जुड़े कई तरह के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बिहार के एक नगर निगम के बेतुके फरमान को लेकर आलोचना का जी रही है। यह निर्णय न केवल बेतुका है बल्कि हास्यास्पद भी है। बिहार के सासाराम के नगर निगम ने शिक्षकों से सड़कों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की गिनती करने को कहा है। दरअसल, अदालत के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों की इस बाबत जवाबदेही तय की गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों व गिरते परीक्षा परिणाम के बावजूद शिक्षकों को गैर–शिक्षण कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हर छोटे–बड़े सरकारी अभियान में शिक्षकों की जिम्मेदारी लगाना प्रशासनिक विफलता को भी उजागर करता है। कभी जनगणना, कभी चुनावी इयूटी तो कभी आपदा सर्वेक्षण, और अब कुत्तों की गिनती का बेतुका काम शिक्षकों के जिम्मे लगा दिया गया है। दरअसल, बिहार के शिक्षक विषम परिस्थितियों के चलते पहले ही अत्यधिक दबाव में हैं। जिसके कारण वे शैक्षणिक जिम्मेदारियों व गैर–शिक्षण दायित्वों के लगातार बढ़ते बोझ के बीच संतुलन बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हर इस तरह का व्यवधान कक्षा के समय, पाठ योजना और छात्रों की सहभागिता को गहरे तक प्रभावित करता है। निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा बच्चे के विकास की नींव रखती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहता है। वर्षों से पेश की जा रही एएफडीआर रिपोर्टों में कई बार उजागर किया गया है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम देश में सबसे कमजोर रहा है। जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जब पहले ही बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है तो शिक्षकों को एक और गैर–शैक्षणिक कार्य के लिये कक्षाओं से बाहर निकालना, निस्संदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि यह आदेश कई वास्तविक खतरों से भरा है। आवारा कुत्तों की गिनती करना शिक्षण के कागजी कार्य के समान सहज नहीं है। निश्चित रूप से अनेक शिक्षक ऐसे होंगे जो कुत्तों से डरते भी होंगे। खासकर शिक्षिकाओं के लिये यह कार्य खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग इस गणना प्रक्रिया में वास्तविक खतरों का सामना भी कर सकते हैं। इस बात का संकेत शीर्ष अदालत की टिप्पणी में भी मिलता है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी कुत्ते के मन को पढ़ना या यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई जानवर कब आक्रामक हो जाएगा। निश्चित रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, उनकी सुरक्षा के लिये भी चुनौती होगी। खासकर तब जब आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं और रेबीज से होने वाली जीवन क्षति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में नगर निगम के आदेश की तात्कालिकता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण और जन सुरक्षा उपायों को लागू करने में नगरपालिकाओं की विफलता पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद एक स्थानीय निकाय ने अपनी मूल जिम्मेदारी शिक्षकों पर थोपकर इसका जवाब दिया है। निश्चित रूप से यह अपनी जिम्मेदारी से पछा झाड़ने जैसा है। निर्विवाद रूप से इस बेतुके आदेश का तत्काल प्रभाव से रद्द करने की जरूरत है।

डिजिटल राजस्थान का उदय और स्टार्टअप से आगे वैश्विक टेक हब बनने की उड़ान

(लेखक – कांतिलाल मांडोट)

जयपुर के जेईसीसी में शुरू हुआ राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उस बदलते राजस्थान का घोषणापत्र है, जो अब अपनी पहचान रेगिस्तान, किलों और पर्यटन से आगे बढ़ाकर तकनीक, नवाचार और वैश्विक उद्यमिता के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। जिस राज्य को कभी आईटी और स्टार्टअप की दौड़ में पीछे माना जाता था, वहीं राजस्थान आज यह आत्मविश्वास के साथ कहने की स्थिति में है कि दुनिया के कई देशों जितनी अपॉरच्युनिटी अकेले यहां मौजूद है। आईटी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठीड़ के शब्द केवल उत्साहवर्धक वक्तव्य नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत का प्रतिबिंब हैं।

तीन दिन तक चलने वाले इस समिट में 1,200 से अधिक वैश्विक कंपनियों के फाउंडर, सीईओ और निवेशकों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि राजस्थान अब निवेशकों की नजर में एक रंगीन और भरोसेमंद डेस्टिनेशन बन चुका है। 20 से अधिक यूनिर्कोंन और सूनिर्कोंन स्टार्टअप्स के संस्थापकों का एक मंच पर आना इस इकोसिस्टम की परिपक्वता को दर्शाता है। यहां हुए एमओयू केवल कागजी समझौते नहीं हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में रोजगार, तकनीकी विकास और आर्थिक विस्तार की नींव हैं।

राजस्थान का स्टार्टअप सफर अब शुरुआती प्रयोगों से निकलकर स्थिर विकास के दौर में प्रवेश कर चुका है। आईटी सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर द्वारा साझा किए गए आंकड़े इस बदलाव की कहानी खुद बयां करते हैं। 7,300 से अधिक स्टार्टअप्स को सुविधा, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 42,000 से ज्यादा नौकरियां केवल सख्याएं नहीं हैं, बल्कि यह उस विश्वास का प्रमाण हैं जो उद्यमियों और निवेशकों ने राज्य पर जताया है। यह सफलता रातोरात नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे निरंतर नीति समर्थन, मजबूत ई–गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की अहम भूमिका रही है। हालांकि, इस समिट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश स्टार्टअप से आगे की संभावनाओं पर केंद्रित है।



प्रेम और दया से ही प्रसन्न होंगे ईश्वर

ईश्वर को खुश करने के लिए लोग तरह–तरह के उपाय करते हैं। मंत्र साधक लाखों बार मंत्र जप करते हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग मंदिर जाकर ईश्वर की पूजा करते हैं। धूप–दीप आरती से भगवान को प्रसन्न करने की भी कोशिश करते हैं। इतना करने के बाद भी यह पता नहीं होता कि ईश्वर हमें प्यार करता है या नहीं। प्रेम में सफलता तभी मिलती है जब हमें जिसे प्यार करते हैं वह हमें प्यार करे। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जिससे ईश्वर आपको प्यार करे। यह काम पूजा–पाठ और

मंत्र जप से भी आसान है। सभी धर्म एक बात पर सहमत हैं कि प्रेम और दया यह दो ऐसे साधन हैं जिसकी बदलते हम ईश्वर को मजबूर कर सकते हैं कि वह हमें प्यार करे। प्रेम और दया ऐसी चीज हैं जिसके लिए न तो धन की जरूरत पड़ती है और न ही किसी दूसरे साधनों की। यह अपने आप में पूर्ण और पवित्र है।

हम किसी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बदले में हमें भी प्रेम मिलता है। इसका कारण यह है कि जिसके प्रति हम प्रेम दर्शाते हैं उसके हृदय में मौजूद आत्मा जो ईश्वर का स्वरूप होता है वह प्रसन्न होता है और बदले में

हमें अपने प्रेम की अनुभूति कराता है। गीता, कुरान अथवा बाइबल सभी में दया को ईश्वर को पाने का माध्यम बताया गया है। ईश्वर को फूल, फल अथवा मंत्र से ध्यान करने का उद्देश्य भी दया है कि हमारा मन निर्मल हो और मन में दया की भावना बढ़े। जिसने दया करना सीख लिया वह ईश्वर का पुत्र हो जाता है। ईसा मसीह, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, साईं सभी ने अपने जीवन में दया का अनुपम परिचय दिया। अपने इसी गुण के कारण ईश्वर ने इन्हें प्यार किया और ईश्वरीय शक्ति इनमें समाहित हो गयी।

वेनेजुएला पर ट्रंप की सख्ती- नया वैश्विक टकराव

(लेखक- सनत जेन)

वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया आक्रामक कार्रवाई ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति एवं सामरिक तनाव को तेज कर दिया है। प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना, समुद्री मार्गों पर निगरानी बढ़ाना और कश्चित तौर पर रूस से जुड़े जहाज की जसी जैसे कदम केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं हैं। इनके दूरगामी अंतरराष्ट्रीय प्रभाव जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। यह घटनाक्रम स्पष्ट संकेत देता है, अमेरिका, लैटिन अमेरिका क्षेत्र में अपने वर्चस्व को आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ट्रम्प कब्जा करना चाहते हैं। भले ही इसके लिए रूस और चीन के साथ सीधा टकराव लेने की ट्रंप की सोच है। अमेरिका और वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी और अर्थव्यवस्था पर जो संकट देखने को मिल रहे हैं उसके बाद यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी डॉलर मुद्रा तथा वैश्विक व्यापार के वर्चस्वको बनाए रखना चाहता है। उसके लिए ट्रंप अंतिम

लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रम्प ने टेरिफ के बहाने जो नया खेल खेला था। उसमें वह असफल हो गए हैं। अमेरिका में मंहगाई और आर्थिक स्थिति पर इसके दुष्परिणाम दिखने लगे हैं। इससे बचने के लिये अब ट्रम्प ने वेनेजुएला का मुद्दा खड़ा करके अमेरिका में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते है? वेनेजुएला लंबे समय से रूस और चीन का रणनीतिक सहोदर है। रूस ने वहां ऊर्जा, हथियार और सैन्य सहयोग किया है। जबकि चीन ने कर्ज, बुनियादी ढांचा और तेल समझौतों के जरिए अपनी गहरी पैठ बनाई है। रूस और चीन के हथियार भी वेनेजुएला में है। ऐसे में किसी रूसी जहाज की जमि केवल एक कानूनी या तकनीकी कार्रवाई के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इस कार्रवाई को रूस के प्रभाव को खुली चुनौती के रूप में ही देखा जाएगा। मांसको ट्रंप की इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता पर हमला बताकर कूटनीतिक विरोध, जवाबी प्रतिबंध या समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने जैसे कदम उठा सकता है। हालांकि रूस सीधे सैन्य टकराव से बचना हुआ दिख रहा है। समय आने

पर इसकी प्रतिक्रिया बड़े रूप में हो सकती है। इससे इनाकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया के देशों में अमेरिका, विरोधी मंचों पर इस मुद्दे का जोर–शोर से उठाना है। चीन का रुख अपेक्षाकृत संतुलित होते हुए भी व्यापारिक दृष्टिकोण से दीर्घकालिक होगा। बीजिंग आमतौर पर प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद और संप्रभुता के सिद्धांतों की बात करते हुये इस समस्या के समाधान की कोशिश करेगा, ऐसी संभावना देखने को मिलती है। अमेरिका की कार्रवाई को चीन एकतरफा दबाव नीति करार देकर वैश्विक मंच पर अमेरिका को अलग–थलग करने की कोशिश करेगा। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न बंघों तथा वैश्विक व्यापार अधिकरण की नीति को लेकर अपना विरोध दर्ज करा सकता है। इसके साथ चीन वेनेजुएला में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से वेनेजुएला की मदद रूस के साथ तालमेल कर ट्रंप की दादागिरी को चुनौती देने का काम कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक प्रभाव तेल बाजारों,समुद्री व्यापार,

वैश्विक व्यापार और विकासशील देशों की आर्थिक एवं विदेश नीति पर पड़ना तय है। वह देश जो अमेरिकी प्रतिबंधों से असहमत हैं। वह चीन–रूस खेमे की नीतियों की ओर झुक सकते हैं। अमेरिका समर्थक देश भी ट्रंप की इस तरह की कार्यवाही के खुले समर्थक नहीं है। इसका असर नाटो देश और युरोपियन संगठन में भी देखने को मिल रहा है। वह ट्रंप की इन नीतियों का कितना समर्थन करेगे, वर्तमान में कहना मुश्किल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की नीतियां आ रही हैं। उसके बाद दुनिया एक बार फिर आर्थिक एवं सामरिक धुंकीकरण की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। विकासशील देश एवं वेनेजुएला जैसे देश महाशक्तियों की रस्साकशी का मैदान बन रहे हैं। यह स्थिति वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सारी दुनिया के सामने है। अमेरिका की इस कार्रवाई से वैश्विक व्यापार संधि के बाद जो आर्थिक परिवर्तन सारी



दुनिया के देशों में देखने को मिला था। निश्चित रूप से वह तेजी के साथ सिमटने लगेंगे। जिसका दुष्परभाव आर्थिक मंदी के रूप में जल्द ही सामने आ सकता है। इसको लेकर तरह–तरह की वैश्विक चिंताएं सामने आने लगी हैं।

संक्षिप्त समाचार

यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ट्रंप के दूत विटकोफ से मिले जेलेंस्की, समर्थन के लिए यूएस को कहा धन्यवाद

पेरिस, एजेंसी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को पेरिस में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही दोनों पक्षों ने सुरक्षा गारंटी, युद्धविराम की निगरानी और देश के पुनर्निर्माण जैसे अहम मुद्दों पर विचार किया। इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और इसे युद्ध समाप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका सुरक्षा गारंटी, युद्धविराम की निगरानी और देश के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए तैयार है। आगे जेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि सात जनवरी को पेरिस में दोनों देशों की टीमों फिर से सुरक्षा गारंटी और युद्ध समाप्ति के लिए बुनियादी ढांचे पर काम जारी रखेगी। बता दें कि इस बैठक में यूक्रेन की ओर से कार्यालय प्रमुख किरिलो बुडनोव, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रूस्तेम उमेरोव, जनरल आंद्रैइ ह्लातोव, कार्यालय के पहले उप प्रमुख सर्गी किसलित्स्या और राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार ओलेक्सान्द्र बेवज शामिल थे। वहीं इस बैठक के बाद अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने कहा कि उनकी टीम ने यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल और 'कोएलिवान ऑफ द विलिंग' के साथ बैठक की, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को आगे बढ़ाया जा सके। अब बात अगर बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बात करें तो ट्रंप की तरफ से जैरेड कुशनर, जनरल एलेक्स ग्रिंकेविच, एम्बेसडर चार्ल्स कुशनर और डेविड हाउस सलाहकार जोश गुर-बनाम इस बैठक में शामिल थे।

मादुरो की गिरफ्तारी के समय वेनेजुएला के 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, कुल आंकड़ा 50 के पार

कराकास, एजेंसी। वेनेजुएला की सेना ने बताया है कि शनिवार को अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में वेनेजुएला के कम से कम 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए। इससे मरने वालों की आधिकारिक संख्या करीब 56 हो गई है। इनमें आम नागरिक और सैन्यकर्मियों दोनों शामिल हैं। वेनेजुएला के अंटीनी जनरल तारेक विलियम साब ने मंगलवार को कहा कि दर्जनों अधिकारी और नागरिक मारे गए और अभियोजक इन मौतों की जांच करेंगे। साब ने अमेरिकी अभियान को युद्ध अपराध करार दिया। इससे पहले क्यूबा की सरकार ने रविवार को एलान किया कि अमेरिकी अभियान में वेनेजुएला में काम कर रहे उसके 32 सैनिक और पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। क्यूबा ने कहा कि ये सैनिक वेनेजुएला में काम कर रहे थे। वेनेजुएला की सेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अमेरिकी हथेलों में मारे गए सैनिकों की तस्वीरें दिख रही हैं। शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक विशेष सैन्य अभियान के तहत हमला किया। इस कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फारकास को राजधानी काराकास से पकड़ लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक यूट्यू चैनल से बातचीत में कहा था कि इस ऑपरेशन में अमेरिका की तरफ कोई मौत नहीं हुई, सिर्फ कुछ सैनिक घायल हुए। ट्रंप ने इसे बेहद जटिल लेकिन सफल ऑपरेशन बताया और अमेरिकी सेना की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब वेनेजुएला को अस्थायी रूप से चलाएगा, जब तक वहां सुरक्षित और व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता।

कनाडा में मोहाली के स्टूडेंट की मौत : पैदल ही जा रहा, कार ने मारी टक्कर, पुलिस खंगाल रही डैशकैम फुटेज

मोहाली, एजेंसी। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में एक सड़क हादसे में पंजाब के मोहाली जिले की लालडू मंडी निवासी 22 वर्षीय छात्र अरमान चौहान की मौत हो गई। यह घटना 5 जनवरी को ओंटारियो के हाईवे-401 पर कामेह टाउनशिप के पास हुई। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते ओंटारियो प्रोविशियल पुलिस (ओपीपी) मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, अरमान अपने एक दोस्त के साथ मोर्नट्रयल से टोरंटो की ओर जा रहा था। हालांकि, हादसे के समय अरमान के पैदल चलने की बात सामने आई है। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह व्यस्त हाईवे पर पैदल किन परिस्थितियों में पहुंचा। जांच एजेंसियां इसी बिंदु को लेकर असमंजस में हैं। ओंटारियो प्रोविशियल पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे की पश्चिमी लेन में एक कार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मारी है। मार के पर पश्चिमी पुलिस को मीडियन के पास एक कार खड़ी मिली। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अरमान की जान उसी कार की टक्कर से गई या किसी अन्य वाहन की चपेट में आने से। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और डैशकैम फुटेज के जरिए पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

अमेरिका पहुंचेगा वेनेजुएला का 50 मिलियन बैरल तेल, दोनों देशों को होगा फायदा : ट्रंप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 मिलियन से 50 मिलियन बैरल प्रतिबंधित तेल सौंपेगी। ट्रंप के अनुसार, यह कदम वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लोगों के हित में होगा। ट्रंप ने ट्यूथ सोशल पर बताया कि यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और वह व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि राजस्व का उपयोग कैसे किया जाता है। उन्होंने लिखा कि इस पैसे का उपयोग वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना पर तुरंत अमल करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार, तेल को स्टोरेज जहाजों पर लोड किया जाएगा और सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका में अनलॉडिंग डॉक तक पहुंचाया जाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि तेल बाजार कीमत पर ही बेचा जाएगा और इससे मिलने

वाले धन पर नियंत्रण अमेरिका के राष्ट्रपति के पास रहेगा। यह घोषणा अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद आई है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया और कारागार में सत्ता परिवर्तन हुआ। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अब वेनेजुएला में तेल, व्यापार और सुरक्षा जैसे मामलों में शर्तें अमेरिका तय करेंगी। ट्रंप के इस बयान पर पूरी दुनिया का ध्यान गया, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। हालांकि, प्रतिबंधों के खराब प्रबंधन और निवेश की कमी के कारण वहां तेल उत्पादन काफी गिर गया है।

गौरतलब है कि भारत भी एक समय वेनेजुएला का बड़ा तेल खरीदार था, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते 2019 में भारतीय रिफाइनरियों को वहां से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। तब से, भारत मध्य पूर्व, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका से



तेल पर अधिक निर्भर हो गया है। अगर वेनेजुएला का इतना बड़ा तेल अमेरिका भेजा जाता है, तो वैश्विक कच्चे तेल के प्रवाह का स्वरूप बदल सकता है। वेनेजुएला का भारी तेल अमेरिका के खाड़ी तट की रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जो पहले लैटिन अमेरिका और कनाडा से तेल आयात पर निर्भर थीं।

इस योजना के आगे बढ़ने पर चीन तक पहुंचने वाले वेनेजुएला के तेल की मात्रा भी कम हो सकती है, क्योंकि अभी चीन वहां

का सबसे बड़ा खरीदार है। वैश्विक तेल आपूर्ति में किसी भी बदलाव से कीमतों और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों में इस पर खास नजर रखी जाती है, क्योंकि देश को बड़ी मात्रा में आयातित ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ता है।

ट्रंप ने इस कदम को आर्थिक और रणनीतिक फैसला बताया है। उनका कहना है कि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का ज्यादा नियंत्रण होने से आरंभिक नेटवर्क कमजोर होगा और

क्षेत्र में स्थिरता आएगी। ट्रंप के अनुसार, इस योजना को तुरंत लागू किया जाएगा।

वेनेजुएला के तेल सेक्टर में निवेश करेगा अमेरिका : मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के खराब हो चुके तेल ढांचे को ठीक करने के लिए अबर्बो डॉलर का निवेश करेंगी। इससे वेनेजुएला को दोबारा तेल उत्पादन से कमाई शुरू करने में मदद मिलेगी। प्लोडिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब तेल बेचने के कारोबार में है और अन्य देशों को भी तेल सप्लाई करेगा। उन्होंने कहा कि खराब ढांचे की वजह से वेनेजुएला खुद ज्यादा तेल नहीं निकाल पा रहा था। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह कहा था कि हमें डेल्टी रोज़िज़न के जरिए वेनेजुएला तक पूरी पहुंच चाहिए। ट्रंप ने वेनेजुएला को मरा हुआ देश बताते हुए कहा कि उसे दोबारा खड़ा करना जरूरी है।

कोलंबिया के राष्ट्रपति की ट्रंप को धमकी: कहा- हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ



उन्होंने 1990 के दशक में हथियार छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई थी कि अब कभी बंदूक नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो वे फिर से हथियार उठा सकते हैं।

उत्प ने कोलंबिया को बीमार देश बताया था : इससे पहले ट्रंप ने कोलंबिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि कोलंबिया एक बीमार देश है और वहां एक ऐसा शख्स शासन कर रहा है जो कोकोन बनाकर अमेरिका भेजता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह राष्ट्रपति ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह बयान भी दिया कि कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना उन्हें एक अच्छा विचार लगता है।

कोलंबिया बोला- किसी को धमकी देना सही नहीं : कोलंबिया सरकार ने इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में बातचीत, सहयोग और आपसी सम्मान में विश्वास रखती है। सरकार ने साफ शब्दों

में कहा कि किसी भी देश को धमकी देना या ताकत का इस्तेमाल करना सही नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर महीने में ट्रंप प्रशासन ने कोलंबियाई राष्ट्रपति पेद्रो और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर ड्रा तस्करी से जुड़े संबंधों के आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए थे। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश माना जाता है। कोकीन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोका पौधा कोलंबिया, पेरू और बोलीविया जैसे देशों में उगाया जाता है।

क्वाइट हाउस ने मादुरो से जुड़ा वीडियो शेयर किया : क्वाइट हाउस ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें मादुरो के पुराने बयानों और अमेरिकी कार्रवाई के वीडियो दिखाए गए। इस वीडियो में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की टिप्पणी भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मादुरो को मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे गंवा दिया और अब उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। इस वीडियो में मादुरो को अमेरिका को चुनौती देते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही उस सैन्य कार्रवाई की फुटेज भी शामिल है, जिसमें अमेरिकी सेना ने मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को पकड़ने के लिए छाप मारा। यह वीडियो कुल 61 सेकंड का है। वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप की वेनेजुएला पर की गई कार्रवाइयों के वीडियो शामिल हैं।

नेपाल में ओली-प्रचंड और देउबा की पार्टियों में गठबंधन संभव

सीट बंटवारे और स्ट्रैटजी पर बातचीत जारी, 20 दिन बाद ऊपरी सदन का चुनाव

काठमांडू, एजेंसी। नेपाली में तीन पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की पार्टियां गठबंधन की तैयारी कर रही हैं। ये गठबंधन संसद के ऊपरी सदन 'राष्ट्रीय सभा' के लिए चुनाव के लिए हो सकता है। इस गठबंधन में मधेश क्षेत्र की पार्टी को भी शामिल करने पर विचार हो रहा है। नेपाली अखबार द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, नेपाली कांग्रेस, सीपीएम-यूएमएल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे और साझा रणनीति पर बात हो रही है। यह चुनाव 25 जनवरी को होना है। राष्ट्रीय सभा में कुल 59 सदस्य होते हैं। इनमें से हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। इस बार 4 मार्च को 18 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन्हीं खाली होने वाली सीटों को भरने के लिए चुनाव कराया जाएगा।



शुरुआती बातचीत में यह बात सामने आई है कि कांग्रेस को 7 सीटें, यूएमएल को 6 सीटें, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 4 सीटें और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को 1 सीट मिल सकती है। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। वहीं यूएमएल ने भी अपने उम्मीदवार तय करने के लिए मंगलवार को पार्टी सचिवालय की बैठक बुलाई है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को बुधवार या 17 जनवरी को नामांकन दाखिल करना होगा। राष्ट्रीय सभा में कुल

59 सदस्य होते हैं। इनमें से 56 सदस्य चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, जबकि 3 सदस्य सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत होते हैं। इन मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक महिला होना जरूरी होता है। राष्ट्रीय सभा में कुल 59 सदस्य होते हैं। इनमें से 56 सदस्य चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, जबकि 3 सदस्य सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत होते हैं। इन मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक महिला होना जरूरी होता है।

आम चुनाव के लिए भी बातचीत जारी : कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड्का ने बताया कि संविधान बनाने में शामिल राजनीतिक ताकतें राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए एकजुट होने पर सहमत हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा की ओर से खड्का ने पहले ही केपी शर्मा ओली से गठबंधन को लेकर बातचीत की थी। हालांकि कांग्रेस और यूएमएल के बीच आने वाले संसदीय चुनावों के लिए भी गठबंधन की चर्चा चल रही है, लेकिन इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं। इस दिन देश के नागरिक संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के लिए मतदान करेंगे, जिसमें कुल 275 सदस्य चुने जाते हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी, चोरी के शक में पीछा, नहर में छलांग लगाते से गई जान



ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर लश्करी हमलों की घटनाएं रकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी के संदिह में भीड़ के पीछा करने से बचने के लिए 25 वर्षीय हिंदू युवक मिथुन सरकार ने नहर में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार दोपहर भंडारपुर गांव के निवासी मिथुन का शव बरामद किया। यह घटना पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की जा रही हिंसा में तीव्र वृद्धि के बीच हुई है। मिथुन सरकार की मौत पिछले कुछ दिनों में सामने आई क्रूर हमलों की श्रृंखला में यह नई घटना है।

हिंदू, बौद्ध और ईसाई एकता परिषद ने एक बयान जारी कर दिसंबर महीने में कम से कम 51 लश्करी घटनाओं का खुलासा किया है, जिनमें 10 हत्याएं शामिल हैं। परिषद ने आगजनी, बलात्कार और लूटपाट के मामलों का विस्तृत विवरण देते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की है कि ये अत्याचार 12 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले की अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होते हैं। परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश ने पहले भी

राजनीतिक उथल-पुथल का सामना किया है, लेकिन वर्तमान समय में संस्थागत कमजोरी और बढ़ती सांप्रदायिक चिंता का खतरनाक संयोग देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब उस समय हो रहा जब देश 12 फरवरी 2026 को होने वाले संसदीय चुनावों की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना सरकार के 2024 में गिरने के बाद अंतरिम सरकार के कार्यालय में अल्पसंख्यकों पर हमलों ने तेजी आई है।

पिछले कुछ दिनों में हुई अन्य घटनाएं... 5 जनवरी को जैशोर जिले में हिंदू व्यापारी और सामान्यार पात्र के कार्यवाहक संपादक राणा काति बैरागी की गोली मारकर हत्या 5 जनवरी को ही सिरागढ़ी में किराने की दुकान मालिक गोर्गी पकवर्ती की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या 3 जनवरी को थरिखपुर जिले में खोकाज चंद दास पर हमला, हलाज के दौरान अस्पताल में मौत इससे पहले दिसंबर में राजबारी में अंगुत मंडल की पीट-पीट कर हत्या और मजमनसिर में दीपू चंद दास की गोद द्वारा पीटकर हत्या कर शव जलाने की घटनाएं सामने आई थीं।

पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों को बम से उड़ने की धमकी, मच गया हड़कंप

मोगा (एजेंसी)। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों फिरोजपुर और मोगा को आरडीएक्स से उड़ने की धमकी मिली है। इसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है और कोर्ट परिसर के गेट बंद कराए गए हैं। जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेल भेज कर धमकी दी गई है कि मोगा और फिरोजपुर कोर्ट परिसर को आरडीएक्स के साथ उड़ा दिया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन फिरोजपुर के प्रधान वकील लवजीतपाल सिंह दूरना ने संपर्क करने पर बताया कि उन्हें माननीय जज साहिब द्वारा यह संदेश दिया गया है कि फिरोजपुर कोर्ट परिसर को आरडीएक्स के साथ उड़ने की धमकी मिली है। यह देखकर एहतियात के तौर पर कोई भी वकील, वरकॉ या वलाइंट कोर्ट परिसर में ना दाखिल ना हो। उन्होंने बताया कि जुडिशल अधिकारी के आदेश को मानते हुए जिला बार एसोसिएशन फिरोजपुर के वकील, वरकॉ और वलाइंट वापस आ गए हैं। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर कोर्ट परिसर में पुलिस द्वारा डोंग स्काड और बंब निरोधक टीमों को साथ लेकर सर्व ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने 4 किलो का आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किया

राजौरी (एजेंसी)। राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण आतंकवादी साजिश को नाकाम कर 4 किलो का संहतिथ इम्प्रोविज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद कर निष्क्रिय किया। यह सफलता सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मिली, जो विश्वसनीय टिप-ऑफ के आधार पर डोरी माल के कलर क्षेत्र के घने जंगल में शुरू किया। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेराबंदी कर गहन तलाशी अभियान शुरू किया। जंगल वाले इलाके में उन्नत पहचान तकनीकों का उपयोग करते हुए सैनिकों और पुलिस ने दबे हुए संदिग्ध सामान का पता लगा लिया। जांच में यह पुष्टि हुई कि यह करीब 4 किलो का परिष्कृत आईईडी था, जो कि अगर विस्फोट किया जाता, तब गंभीर नुकसान हो सकता था। पास में खाली खोल भी मिले, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया।आईईडी को निर्यातित विस्फोट (कंट्रोल्ड ब्लास्ट) के माध्यम से निष्क्रिय किया, जिससे आसपास के नागरिक सुरक्षित रहे।ऑपरेशन के बाद साइट को साफ किया, लेकिन अतिरिक्त संदिग्धों या डिवाइस की जांच जारी है। सुरक्षा बल क्षेत्र में गश्त तेज कर सुरक्षा बनाए रखने में जुटे हैं। इस बीच, जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद संयुक्त बलों ने तलाशी अभियान और बढ़ा दिया। यह कार्रवाई दोनों जिलों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित हुई।

त्रिपुरा में सुरक्षा बलों ने छह लाख गांजे के पौधे नष्ट किए... अनुमानित कीमत 145 करोड़

त्रिपुरा (एजेंसी)। त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले में सुरक्षा बलों ने छह लाख गांजे के पौधे नष्ट किए, जिससे 10 दिनों में कुल करीब 30 लाख पौधे नष्ट हो गए। इन पौधों की अनुमानित कीमत 145 करोड़ आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, दिन भर चले संयुक्त ऑपरेशन में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने करीब 200 एकड़ क्षेत्र में 65 प्लॉटों पर उमर गए पौधों को नष्ट किया। नष्ट किए गए पौधों की कीमत लगभग 36 करोड़ रुपये है। ऑपरेशन में त्रिपुरा पुलिस, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, असम राइफल्स, बीएसएफ, दन विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर काम किया। यह अभियान सोनमुरा, मेलागढ़ और कलामचीरा के तहत आने वाले गांवों में हुआ, जो बांग्लादेश सीमा के पास हैं। असम राइफल्स ने कहा कि यह ऑपरेशन अवैध गतिविधियों को रोकने और क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने में सहयोगी एजेंसियों के संपातित प्रयासों को दिखाता है।इससे पहले, सुरक्षा बलों ने 414 एकड़ पहाड़ी जमीन पर फैले 23 लाख से अधिक गांजे के पौधे नष्ट किए थे, जिनकी कीमत करीब 108 करोड़ रुपये थी। इस तरह अन्य जिलों जैसे उनाकटोटी, दक्षिण त्रिपुरा और खोवाई में भी कई लाख पौधे नष्ट किए गए। वहीं सुरक्षाबलों ने अवैध खेती में शामिल कई लोगों को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि कई बार जंगल और सरकारी जमीन पर कब्जा करके गांजे की खेती की जा रही थी। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए नशीले पदार्थ की खेती, रखरखाव, बिक्री या सेवन गैर-कानूनी है, और उल्लंघन करने पर 20 साल तक जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल के ट्रक से 12,600 बोतल एस्कॉफ कफ सिरप, 16,000 रुपए और मोबाइल जब्त किए गए, जिसमें दो लोग गिरफ्तार हुए।

कठुआ के कहोग गांव में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़

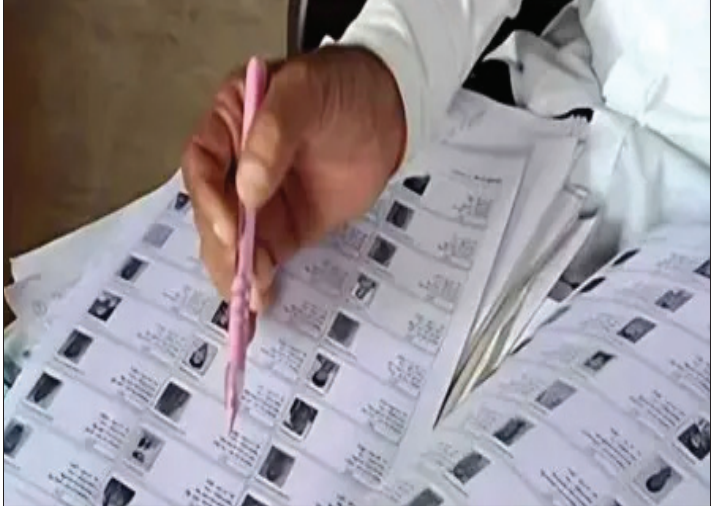
कठुआ (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ के बिलावर क्षेत्र के कहोग गांव में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों के अनुसार, जैरा-ए-मोहम्मद से जुड़े तीन आतंकवादी गांव में छिपे हुए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल तलाशी अभियान जारी हैं। मुठभेड़ बुधवार शाम शुरू हुई, जब दो से तीन आतंकवादियों को मौजूदगी की सूचना मिली। जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर कार्रवाई की। मुठभेड़ में एक सुरक्षाकर्मी को पैर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिकारी बताते हैं कि घने जंगल और दुर्गम इलाके में रात भर घेराबंदी के बाद तलाश अभियान फिर से शुरू किया। धनु परोल-कमाध नाला क्षेत्र में हवाई निगरानी के साथ अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। जम्मू जौन के आईजीपी भीम सेन तूती ने बताया कि अंधेरा और कठिन भूभाग होने के बावजूद एसओजी आतंकवादियों से लगातार मुकाबला कर रही है। सीआरपीएफ की टीम भी संयुक्त अभियान में शामिल है। मुठभेड़ करीब एक घंटे चली, इसके बाद गोलीबारी रुक गई। फिलहाल यह जानकारी नहीं है कि कोई आतंकवादी हताहत हुआ या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक महीने से सेना, बीएसएफ, पुलिस और सीआरपीएफ सीमा क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। वे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों की पहचान कर रहे हैं और सांभा एवं कठुआ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास राहत तेज कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले बीएसएफ, सीमा पुलिस और ग्राम रक्षा गार्ड समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस कार्रवाई का मकसद न केवल आतंकवादियों को पकड़ना बल्कि सीमा सुरक्षा मजबूत करना और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कठुआ जिले के दुर्गम इलाके में सक्रिय आतंकवादी समूहों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगातार चल रही है।

शुक्रवार 09 जनवरी 2026

उप्र चुनाव में मतदाता सूची से 2.89 करोड़ नाम हटे, भाजपा ने शुरू किया डैमेज कंट्रोल अभियान

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक सरगमों तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ताजा ड्राफ्ट के अनुसार, प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 18.70 प्रतिशत है, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। इस भारी कटौती के बाद अब उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नाम हटाए जाने के पीछे मुख्य रूप से मतदाताओं की मृत्यु, उनके निवास स्थान में बदलाव (पलायन), लंबे समय से अनुपस्थिति या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होना जैसे तकनीकी और वास्तविक कारण शामिल हैं। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में वोट कटने से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस स्थिति से निपटने और चुनावी गणित को दुरुस्त करने के लिए तत्काल डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर काम शुरू कर दिया



है। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण वरूचुअल बैठक की। पार्टी ने अपने संगठन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय हों और हर पोलिंग बूथ पर कम से कम

200 नए मतदाताओं के नाम जुड़वाना सुनिश्चित करें। प्रदेश में कुल 1.77 लाख पोलिंग बूथ हैं और इस लक्ष्य के जरिए पार्टी लगभग 3.5 करोड़ नए और वास्तविक मतदाताओं को सूची में शामिल करने की योजना बना रही है।

भाजपा को इस रणनीति में प्रवासियों और

अभिनेता धर्मेद्र के निधन के बाद सांसद के रुप में काम पर लौटी हेमा... संसद खेल महोत्सव में पहुंची



मुंबई (एजेंसी)। अभिनेता धर्मेद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने पहली बार अपने काम पर वापसी की और उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मुंबई में एक समय कठिन और दुखभरा रहा, लेकिन अब वे अपने कर्तव्य और काम पर फोकस कर रही हैं। हेमा ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे मधुरा में आयोजित संसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती दिख रही हैं। वीडियो में उनके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान देखी गई। मधुरा से सांसद हेमा ने लिखा कि मैराथन संसद खेल महोत्सव में राज्य के कोने-कोने से प्रतिभागी विभिन्न खेलों में भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से शूटिंग, कूश्ती और अन्य बहु-विधाओं में कई लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि योगम मोदी की पहल से प्रतिभा को महत्व दिया जा रहा है और अब सभी प्रतिभागियों के

अपने कौशल दिखाने का समान मौका मिल रहा है। मधुरा इसका उदाहरण है कि अब सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। इस पोस्ट पर यूजर्स ने भी हेमा को मुस्कुराते देखकर अपनी खुशी जाहिर की है। एक यूजर ने उन्हें -चट्टन की तरह मजबूत और पवित्र आत्मा वाली- बताया, जबकि दूसरे ने लिखा कि -अपने गम को भुलाकर कर्म ही सच्ची सेवा है।- साथ ही, हाल ही में हेमा ने धर्मेद्र की दो अलग-अलग प्रार्थना सभाओं को लेकर उठे सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह दोनों परिवारों का निजी मामला है। एक प्रार्थना सभा उन्होंने आयोजित की थी, जबकि दूसरी सप्ती देओल के घर रखी गई थी। हेमा मालिनी अब दुख को पीछे छोड़कर अपने कर्म और जनसेवा में लौट आई हैं, और उनकी मुस्कान दर्शकों और फैंस के लिए प्रेरणा बन गई है।

एक भी वोट विभाजित न हो, एक भी वोट कम न हो... का नारा देकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर तीखा हमला कर कहा कि यदि संविधान और आरक्षण को बचाना है, तब पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज को एकजुट होना होगा। उन्होंने मतदाताओं और 'पीडीए संरक्षकों' से अपील की कि आगामी चुनावों में पीडीए समुदाय के वोट किसी भी हालत में विभाजित न हों। उनका स्पष्ट संदेश था कि एक भी वोट विभाजित न हो, एक भी वोट कम न हो-।

सपा नेता अखिलेश यादव ने आशंका जाहिर की कि भाजपा सरकार मतदाता सूचियों में गड़बड़ी कर सकती है और छूटे हुए नामों का दुरुपयोग कर नागरिकों को योजनाओं, नौकरियों, राशन कार्ड, जमीन और अन्य अधिकारों से वंचित कर सकती है। उन्होंने मतदाताओं से अपने वोटर आईडी को नागरिक पहचान का



अहम दस्तावेज मानने और मतदान प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतने की अपील की।

उन्होंने कहा कि वोटों की सुरक्षा केवल सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, रोजगार और संपत्ति की गड़बड़ी कर सकती है। -अपना वोट दर्ज करें, अपना भविष्य बचाएं- के नारे के साथ उन्होंने राष्ट्रपति पद के मनमाने व्यवहार या उत्तराधिकार प्रक्रिया से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पीडीए मिलने के लिए समय मांगा था। साथ ही, टुंप ने यह भी कहा कि रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों के कारण पीएम मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं। टुंप के इन कट्टरनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संतुलित विदेश नीति की वकालत की है। थरूर का कहना है कि किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं और कूटनीति का असली उद्देश्य शत्रुओं की संख्या को कम करना और मित्रों का दायरा बढ़ाना होना चाहिए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे

समाज के लाखों वोट अब भी अलग-अलग हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर कड़ी निगरानी जरूरी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगियों का असली उद्देश्य चुनाव जीतकर सत्ता में आना और फिर भ्रष्टाचार में लिस होना है। उन्होंने कहा कि यदि पीडीए समाज के हाथों से निर्णायक मतदान अधिकार छिन गया, तब उपपीडन और बढ़ेगा तथा दबंग ताकतें मनमाने ढंग से सरकार बनाकर संविधान को कमजोर करेंगी। उनका कहना था कि वोट बचाना ही संविधान, आरक्षण और रोजगार के अधिकारों को बचाने का एकमात्र रास्ता है। इसके पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मसौदा मतदाता सूची से 2.89 करोड़ नाम हटाने पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस -बड़ी साजिश बताकर निष्पक्ष जांच की मांग की।

भारत-अमेरिकी संबंधों पर बोले थरूर- राष्ट्रहित में विकल्प खुले रखना बेहद जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दी गई हालिया टिप्पणियों पर देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। इस संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संतुलित विदेश नीति की वकालत की है। थरूर का कहना है कि किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं और कूटनीति का असली उद्देश्य शत्रुओं की संख्या को कम करना और मित्रों का दायरा बढ़ाना होना चाहिए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे

अमेरिका, दोनों के साथ मधुर संबंध साझा करता है, जबकि चीन के साथ भी कामकाजी रिश्ते बनाए हुए हैं। इसके साथ ही जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत का बढ़ता तालमेल हमारी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार, कूटनीति में सुरक्षित रहने का सबसे बेहतर तरीका है कि सभी के साथ संपर्क के रास्ते खुले रखे जाएं। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया काफी आक्रामक रहा है। हाउस ऑफ़ी सदस्य रिट्नेट पॉपिंगेन समाज से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने मनमाने व्यवहार का दायरा बढ़ाने की मुलाकात के अनुरोध का जिक्र

किया, बल्कि पूर्व में भारत पर आयात शुल्क (टैरिफ) बढ़ाने की चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने अपने संबोधन में यह संकेत देने की कोशिश की कि भारतीय नेतृत्व उनके साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है। हालांकि, कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ट्रंप के ऐसे बयान अक्सर उनके घरेलू राजनीतिक एजेंडे और अमेरिका फर्स्ट की नीति से प्रेरित होते हैं। फिलहाल, भारतीय राजनीतिक हलकों में इस बात पर चर्चा तेज है कि अमेरिका के इस दबावपूर्ण रवैये के बीच भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कैसे बरकरार रखता है।

चेन्नई (एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। दक्षिण भारत में मानसून की विवाद के बावजूद बारिश का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। केरल में आने वाले 72 घंटों के दौरान कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और हवाओं की रफ्तार बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी है। तमिलनाडु में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चेन्नई समेत कई तटीय इलाकों में घने बादल छा रहे और झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा पुदुचेरी और कराईकल जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। देश के मौसम में एक बार फिर

रेड वाली जगह पर पहुंची ममता... मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तब क्या होगा ?

पश्चिम बंगाल (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय देश भर में 15 जगहों पर तलाशी अभियान चला रहा है। यह तलाशी एक संगठित गिरोह के खिलाफ फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही है, जो लोगों को फर्जी नौकरियां देकर ठगी कर रहा था। इसी कड़ी में कोलकाता में इंडियन पॉलिटेक्नल एवशन कमेटी के ऑफिस में ईडी की रेड चल रही थी। तभी वहां पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ...क्या ईडी, अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क, कैडिडेट लिस्ट इकट्ठा करना है?... यह गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता और मेरे पार्टी के सारे कामजात ले जा रहा है। अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तब क्या होगा? एक तरफ, वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर कवाकर सभी वोटर्स के नाम हटा रहे हैं... चुनावों की वजह से, वे मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार सुबह ईडी की टीम साल्टलेक के सेक्टर-5 में आईपीएस के ऑफिस में सर्च कर रही थी। इसी बीच, सेंट्रल एजेंसी की एक और टीम आईपीएस के हेड प्रतीक जैन के घर पहुंची। प्रतीक जैन 7 लाउडन स्ट्रीट में रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने यह सर्च ऑपरेशन इसलिए शुरू किया ताकि पता लगा सके कि आई-पैक का दिल्ली में हुए वित्तीय फर्जीवाड़े से कोई कनेक्शन है या नहीं। ईडी सूत्रों के मुताबिक, यह छाप दिल्ली में कोयला तस्करी मामले में दर्ज एक पुराने केस से जुड़ा है।



इम्तियाज जलील पर हमले से भड़के औवेसी... चुनाव में जनता वोट से जबाव देगी

छत्रपति संभाजी नगर (एजेंसी)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष और सांसद इम्तियाज जलील पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की है। सांसद ओवैसी ने कायदापूर्ण हमला बताकर कहा कि औरंगाबाद की जनता लोकतांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से इसका जवाब देगी। ओवैसी ने कहा कि यह हमला उन लोगों की हताशा को दिखाता है, जिन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस वाई और पूरे औरंगाबाद के लोग एमआईएमआईएम के चुनाव चिह्न 'पतंग' पर वोट देकर साजिश करने वालों को जवाब देने वाले हैं। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से घटना के पीछे शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग



की। इसके एक दिन पहले ओवैसी ने छत्रपति संभाजीनगर में आजाद चौक से बुद्धि लेने तक रोड शो किया और स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।

ओवैसी की पार्टी के सांसद जलील ने बताया कि रैली के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी और मोके पर पुलिस भी मौजूद थी, इसके बावजूद 20 से 25 हथियारबंद लोगों ने रैली पर हमला किया। हमलावरों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और वार्हों को निशाना बनाया,

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 29 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा की है। इसमें बीएमसी, पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम शामिल हैं। मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी।

कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की हालत स्थिर, एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाएं दी जा रही

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोमवार रात सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की हालत स्थिर बनी हुई है। सर गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप ने इसकी जानकारी दी। अध्यक्ष ने बताया कि सोनिया गांधी का इलाज जारी है और वे स्वस्थ हो रही हैं।। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद सोमवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के अध्यक्ष स्वरूप ने बताया कि विस्तृत चिकित्सा जांच के बाद पता चला कि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण के मिले-जुले प्रभाव से सोनिया गांधी के ब्रॉंकियल अस्थमा की समस्या थोड़ी बढ़ी थी। एहतियात के तौर पर डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी और आगे के इलाज के लिए भर्ती करने का फैसला किया। स्वरूप ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और चिकित्सकीय जांच में सामने आया कि ठंड और प्रदूषण के मिले-जुले प्रभाव से उनका ब्रॉंकियल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया था। एहतियात के तौर पर उन्हें आगे की निगरानी और इलाज के लिए भर्ती किया गया। फिलहाल उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है। उनके इलाज के बारे में और जानकारी देकर अस्पताल के अध्यक्ष ने बताया कि सोनिया गांधी इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं और उन्हें एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाएं दी जा रही हैं। स्वरूप ने कहा कि उनकी हालत में सुधार के आधार पर इलाज करने वाले डॉक्टर उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला कर सकते हैं। स्वरूप ने कहा कि फिलहाल उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है।



मौसम का मिजाज: उत्तर भारत में कंपाने वाली ठंड और दक्षिण-पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट

चेन्नई (एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। दक्षिण भारत में मानसून की विवाद के बावजूद बारिश का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। केरल में आने वाले 72 घंटों के दौरान कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और हवाओं की रफ्तार बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी है। तमिलनाडु में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चेन्नई समेत कई तटीय इलाकों में घने बादल छा रहे और झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा पुदुचेरी और कराईकल जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। देश के मौसम में एक बार फिर

बड़ा बदलाव होने के कारण एक तरफ जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाके भीषण शीतलहर और कड़के की ठंड की चपेट में हैं, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, विभिन्न मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।

ओवैसी की पार्टी के सांसद जलील ने बताया कि रैली के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी और मोके पर पुलिस भी मौजूद थी, इसके बावजूद 20 से 25 हथियारबंद लोगों ने रैली पर हमला किया। हमलावरों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और वार्हों को निशाना बनाया,

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 29 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा की है। इसमें बीएमसी, पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम शामिल हैं। मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी।

